



RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 18

प्रति सोमवार, 21 सितंबर 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

सागर शराब कांड ने बढ़ाई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें

■ जहरीली शराब ने बुझाए घरों के चिराग ■ पहले कांग्रेस में अब भाजपा में चला रहे अवैध गोरखधंधे



सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में ससिद्ध जहरीली शराब से हुई मौतों ने मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख नेता खादय, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। क्षेत्र में होने

वाले सभी अवैध धंधों में मंत्री की और इनसे जुड़े गुर्गों का नाम सबसे पहले आता है। शराब कांड को भी ऐसे ही जोड़ा जा रहा है। जब राजपूत कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी इनका नाम अवैध कारोबार से जुड़ता रहा है। आज जब वह भाजपा सरकार में मंत्री हैं तो इनका अवैध गोरखधंधा फिर चल पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि राजपूत का क्षेत्र के शराब माफियाओं से गहरे ताल्लुक है। इनके संरक्षण और शह पर शराब माफिया बेखौफ होकर अपना अवैध कारोबार करते हैं। इससे पहले भी



हमने राजपूत के विभाग में होने वाली राशन वितरण प्रणाली की धांधली को लेकर पोस्ट लिखी थी। पीडीएस व्यवस्था में भी उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, तो निगरानी तंत्र को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी?

मंत्री की जवाबदेही पर उठते सवाल

सागर से जुड़े राजनीतिक विमर्श में मंत्री और स्थानीय नेता गोविंद सिंह राजपूत की प्रशासनिक तथा राजनीतिक जवाबदेही को लेकर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। किसी भी सरकार में मंत्री से यह अपेक्षा रहती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जानकारी समय पर शासन तक पहुंचे। यदि अवैध शराब की बिक्री का नेटवर्क सक्रिय था, तो उसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों तक क्यों नहीं पहुंची? यदि सूचना पहुंची थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि कार्रवाई हुई थी तो इतनी बड़ी त्रासदी को रोकने में वह प्रभावी क्यों नहीं रही? (शेष पेज 2 पर)

विष्णुदेव साय सरकार ने दिया नई तकनीक, स्टार्टअप, कौशल विकास और निवेश को प्रोत्साहन युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में नए अवसरों का विस्तार



-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित करने और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास, स्टार्टअप, नई तकनीक, निवेश और रोजगार को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार की नीतियों में पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, उभरती तकनीक और नवाचार आधारित क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार सृजन को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। राज्य के निवेश पोर्टल के अनुसार फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध है। साथ ही प्रक्रियाओं को सरल बनाने, ऑनलाइन स्वीकृतियों और एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। (शेष पेज 2 पर)

राजीव से राहुल तक: युवाओं पर विश्वास की विरासत

राहुल गांधी के छात्रों से संवाद में कमलनाथ को सुनाई देती है राजीव गांधी के सपनों की गूंज

-विजया पाठक

भारत की राजनीति में युवाओं को केवल भविष्य कहने की परंपरा पुरानी है, लेकिन उन्हें वर्तमान में अधिकार, अवसर और निर्णय की ताकत देने का साहस कुछ ही नेताओं ने दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जब स्व. राजीव गांधी के दौर को याद करते हैं तो उनकी स्मृतियों में एक ऐसे प्रधानमंत्री की तस्वीर उभरती है, जिसने समय से बहुत पहले युवा भारत की क्षमता और आने वाली तकनीकी दुनिया को पहचान लिया था। आज राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' पहल में कमलनाथ उसी सोच और विरासत का नया स्वरूप देखते हैं। कमलनाथ कहते हैं कि राजीव गांधी को उन्होंने बेहद करीब से देखा और उनके साथ काफी काम किया। राजीव गांधी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल उस समय के भारत के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उस भारत की कल्पना करते थे जो आने वाले 20-30



वर्षों में बनने वाला था। उनकी इस कल्पना के केंद्र में भारत का युवा था। यही कारण था कि राजीव गांधी ने युवाओं को केवल भाषणों में महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्हें अधिकार और अवसर देने वाले ऐतिहासिक फैसले किए। उनके कार्यकाल में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। (शेष पेज 2 पर)

युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में नए अवसरों का विस्तार

(पेज 1 का शेष)

नई पीढ़ी के रोजगार के लिए 500 करोड़ रुपये का मिशन

सितंबर 2026 में राज्य मंत्रिपरिषद ने अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के लिए अनुसंधान कौशल विकास करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस मिशन का पूरा नाम Chief Minister Startup and New-Age Industry Preparedness through Up-skilling of New Generation Youth (NIPUN) Mission है। इसके तहत युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप तैयार करने और उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल की प्रमुख विशेषता नई तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था है। राज्य में 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लेब स्थापित करने की योजना है। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती तकनीकों पर व्यावहारिक अनुभव देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 'जीव इंजन' के माध्यम से नई पीढ़ी के रोजगारों के लिए युवाओं को तैयार करने की दिशा में पहल की जा रही है। इससे रोजगार की तैयारी को केवल पारंपरिक प्रशिक्षण तक सीमित करने के बजाय तकनीकी ज्ञान, प्रयोगात्मक सीख और उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है।

स्टार्टअप को आइडिया से बाजार तक पहुंचाने की पहल

छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्वेंशन एंड स्टार्टअप प्रमोशन पॉलिसी 2025-30 लागू की गई है। स्टार्टअप छत्तीसगढ़ के अनुसार नीति का उद्देश्य उद्यमियों को आइडिया के शुरुआती चरण से लेकर सीड फंडिंग और विस्तार तक सहायता उपलब्ध कराना है। इसमें अकादमिक संस्थानों, इनक्यूबेटर्स, निवेशकों और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। नीति के माध्यम से युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करने और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे नौकरी तलाशने वाले युवाओं के साथ-साथ रोजगार देने वाले युवा उद्यमियों के लिए भी अवसर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

आईटी और तकनीकी उद्योगों के लिए नया आधार

जून 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग आईटी पार्क का उद्घाटन किया। इसे दुर्ग-भिलाई क्षेत्र को तकनीकी, नवाचार और स्टार्टअप के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया

है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ सरकार, आईआईटी भिलाई और नगर निगम दुर्ग के सहयोग से विकसित की गई है। आईटी पार्क में आईटी-सक्षम सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास और अन्य उभरती तकनीक से जुड़ी कंपनियों तथा स्टार्टअप के लिए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। आईआईटी भिलाई के साथ अकादमिक और औद्योगिक सहयोग इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। कंपनियों को संस्थान के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, प्रयोगशालाओं और तकनीकी क्षमताओं से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इस प्रकार तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच संपर्क बढ़ाकर युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर स्टार्टअप को प्रोत्साहन

फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ। इसके तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की पहल की गई। इन केंद्रों के माध्यम से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट कृषि जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना है। ईएसडीडी सेंटर से प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एम्पलप्लेमेंट को उत्पाद डिजाइन, प्रोटोटाइप तैयार करने और क्षमता विकास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य बताया गया है। इन पहलों में इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाओं तक पहुंच भी शामिल है।

निवेश के साथ रोजगार को जोड़ने पर जोर

छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में निवेश के साथ रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जून 2026 में केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के हवाले से बताया गया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से जोड़ती है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 11,400 से अधिक युवाओं को पहली नौकरी के प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया। सितंबर 2026 में प्रकाशित एर रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में औद्योगिक विकास नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में 290 परियोजनाओं के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे संभावित रूप से

लगभग 1.9 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना बताई गई। इनमें से 175 परियोजनाओं पर काम शुरू होने की जानकारी भी दी गई है।

रोजगार के पारंपरिक क्षेत्रों में भी नवाचार

युवाओं के लिए अवसर केवल बड़े उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखे जा रहे हैं। राज्य के रोजगार विभाग के पोर्टल पर रोजगार, मेले, प्रशिक्षण और रोजगार मार्गदर्शन की व्यवस्था उपलब्ध है। राज्य के 33 जिलों में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र संचालित होने की जानकारी दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र को रोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे नीति जैसी पहल भी की गई है। राज्य सरकार के प्रकाशन के अनुसार बालोदाबाजार में राज्य की पहली फाइनेंस लेब स्थापित की गई, जहां युवाओं को डिजिटल बैंकिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा गया है।

उद्योग, कौशल और रोजगार का एकीकृत मॉडल

छत्तीसगढ़ में रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयासों की दिशा तीन प्रमुख स्तरों पर दिखाई देती है: पहला, युवाओं को नई तकनीक के अनुरूप कौशल प्रदान करना; दूसरा, स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना; और तीसरा, निवेश एवं औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना। दुर्ग आईटी पार्क, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लेब, 500 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन, स्टार्टअप नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर केंद्र और औद्योगिक नीति इसी व्यापक दृष्टिकोण के अलग-अलग हिस्से हैं। इन पहलों का प्रभाव आने वाले वर्षों में इस बात से आंका जाएगा कि कितने युवाओं को स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार मिलता है, कितने स्टार्टअप सफलतापूर्वक विस्तार करते हैं और राज्य में निवेश वास्तविक औद्योगिक उत्पादन में कितना परिवर्तित होता है। छत्तीसगढ़ सरकार का मौजूदा जोर यही है कि युवाओं को रोजगार की तलाश और उद्यमिता को एक साथ जोड़ने का यह प्रयास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अधिक विविध और तेजगति से बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहा है।

पंचायत उप निर्वाचन के लिए ईवीएम का प्रथम जिला स्तरीय रेंडमाइजेशन संपन्न

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, बालीगढ़। राज्य

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में पंचायत उप निर्वाचन के लिए ईवीएम मशीनों का प्रथम जिला स्तरीय रेंडमाइजेशन कलेक्टर सभागार में किया गया। प्रेक्षक बी.एम. शर्मा (सेवानिवृत्त आईएएस) तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान की उपस्थिति में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। जिले की ग्राम पंचायत सर्वा में होने वाले सरपंच पद के उप निर्वाचन के लिए दो मतदान केंद्रों हेतु ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन किया गया। इनमें शासकीय हाई स्कूल सर्वा तथा शासकीय प्रारंभिक विद्यालय दफाई समचौली मतदान केंद्र शामिल हैं। रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान अपर कलेक्टर अनिल बनवारिया एवं संयुक्त कलेक्टर सुरेश कुमार बरहादिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



सागर शराब कांड ने बढ़ाई मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें

(पेज 1 का शेष)

सागर में फिर वही सवाल क्यों?

सागर की वर्तमान घटना ने पुराने अनुभवों के बावजूद निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा किया है। बंडा क्षेत्र में कथित रूप से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही शराब, नकली पहचान और स्थानीय स्तर पर बिक्की की बात जांच में सामने आई है। पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए और गिरफ्तारियां की हैं। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेही महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि अवैध शराब का कारोबार संगठित रूप से चल रहा था, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी केवल किसी एक पुलिसकर्मी या छोटे अधिकारी की नहीं हो सकती। आवकारी विभाग, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई करके मामला समाप्त कर देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी स्तर पर संरक्षण, मिलीभगत, लापरवाही या सूचना छिपाने के प्रमाण मिलते हैं तो कार्रवाई जिम्मेदारी की वास्तविक सीमा तक पहुंचनी चाहिए।

सवाल कार्रवाई की निष्पक्षता का

सरकार ने मामले में जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश के साथ अवैध शराब के खिलाफ प्रदेशव्यापी कार्रवाई की बात कही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जांच का दायरा किसी व्यक्ति या दल की राजनीतिक सुविधा के अनुसार सीमित न हो। इसमें शराब के निर्माण से लेकर परिवहन, बिक्री, स्थानीय नेटवर्क, लाइसेंस व्यवस्था, आवकारी अधिकारियों की भूमिका और पुलिस की सूचना प्रणाली तक प्रत्येक कड़ी की जांच हो। गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में किसी अधिकारी, कारोबारी या शराब माफिया की मिलीभगत सामने आती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सागर की त्रासदी को केवल

एक शराब कांड मानकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी भूल होगी। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है जो शराब के अवैध कारोबार पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है। मुक्तकों के परिवारों को मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि यह पता चले कि जहरीली शराब उन गांवों तक पहुंची कैसे और उसे रोकने वाली व्यवस्था विफल क्यों हुई। उसी रिपोर्ट से तय होना चाहिए कि दोषी कौन है, लापरवाही किस स्तर पर हुई और किसकी जवाबदेही बनती है।

आंकड़े बताते हैं कि समस्या नई नहीं है

मध्यप्रदेश में अवैध और जहरीली शराब से मौतों का संकट केवल सागर तक सीमित नहीं रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में अवैध/मिलावटी शराब के सेवन से 2016 में 184, 2017 में 216, 2018 में 410, 2019 में 190 और 2020 में 214 मौतें दर्ज हुई थीं। यानी 2016 से 2020 के बीच ही राज्य में 1,214 मौतें दर्ज की गईं। इससे भी पहले 2012-14 के दौरान अवैध/मिलावटी शराब से होने वाली मौतों का राष्ट्रीय स्तर पर अलग से सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध है।

विधायक-मंत्री की जवाबदेही पर उमा भारती ने उठाये सवाल

उमा भारती ने कहा कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उन लोगों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, जो आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थे या उनके साथ उठते-बैठते थे। उन्होंने सागर के स्थानीय नेताओं की भूमिका की जांच की मांग करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विधायक और मंत्री गोविंद सिंह के साथ आरोपी की तस्वीर सामने आने को लेकर भी उमा भारती ने सवाल उठाए।

राहुल गांधी के छात्रों से संवाद में कमलनाथ को सुनाई देती है राजीव गांधी के सपनों की गूंज कमलनाथ को राहुल गांधी के इस प्रयास में राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत की निरंतरता दिखाई देती है। राजीव गांधी ने 18 वर्ष के युवा से कहा था- देश की सरकार चुनने में तुम्हारी आवाज महत्वपूर्ण है

(पेज 1 का शेष)

इसके पीछे सोच साफ थी- यदि 18 वर्ष का युवा देश के भविष्य की जिम्मेदारी उठा सकता है तो उसे देश की सरकार चुनने में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। यह फैसला केवल मतदान की उम्र घटाने का नहीं था, बल्कि करोड़ों युवाओं पर विश्वास व्यक्त करने का निर्णय था।

इसी सोच का दूसरा बड़ा अध्याय था भारत में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के विस्तार को गति देना। उस समय कंप्यूटर को लेकर आशंकाएं थीं, लेकिन राजीव गांधी आने वाले समय को देख रहे थे। उन्होंने तकनीक को रोजगार का विरोधी नहीं, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसरों का माध्यम माना। बाद के दशकों में भारत जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और दूरसंचार के क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल हुआ, उसकी बुनियाद तैयार करने में उस दौर की नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज करीब चार दशक बाद युवा भारत के सामने चुनौतियां का स्वरूप बदल गया है। तकनीक के अवसर बढ़े हैं तो प्रतिस्पर्धा भी कई गुना बढ़ी है। शिक्षा महंगी हुई है, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते हैं, रोजगार की चिंता है और भविष्य को लेकर असुरक्षा भी है। ऐसे समय में कमलनाथ राहुल गांधी की उस पहल को महत्वपूर्ण मानते हैं जिसमें नेता मंच से युवाओं को केवल सुनाता नहीं, बल्कि मंच युवाओं को सौंपकर स्वयं उनकी बात सुनता है।

इस पहल का नाम है: 'छात्रों की गूंज'

पुणे में आयोजित 'छात्रों की गूंज' में राहुल गांधी ने विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं से सीधे संवाद किया। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर, सुरक्षा, सामाजिक दबाव और आदिवासी विद्यार्थियों की समस्याओं तक अनेक मुद्दे युवाओं ने उनके सामने स्वयं रखे। अब 19 सितंबर को यही संवाद इंदौर में होने जा रहा है। 'छात्रों की गूंज' की विशेषता यही है कि यह परंपरागत राजनीतिक सभा से अलग संवाद का मंच बनाने का प्रयास है। यहां सवाल नेता तय नहीं करता, युवा अपनी समस्या स्वयं बताता है। वह बता सकता है कि उसकी पढ़ाई में क्या बाधा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, रोजगार को लेकर उसकी चिंता क्या है और आखिर कौन-सी परिस्थितियां उसे अपने सपनों तक पहुंचने से रोक रही हैं। ऐसे संवाद का महत्व केवल किसी समस्या को सुन लेने तक सीमित नहीं है। जब देश के अलग-अलग हिस्सों के विद्यार्थी अपनी समस्याएं सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखते हैं तो स्थानीय दिखने वाली अनेक समस्याएं राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन सकती हैं। नीति बनाने वालों को आंकड़ों के पीछे छिपी वास्तविक जिंदगी सुनाई देती है और युवाओं को यह भरोसा मिलता है कि लोकतंत्र में उनकी भूमिका केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है- उनकी बात, उनका अनुभव और उनके सुझाव भी मायने रखते हैं।

राजीव गांधी- देश की सरकार चुनने में तुम्हारी आवाज महत्वपूर्ण है

आज राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' के माध्यम से नई पीढ़ी से मानो कह रहे हैं। देश का भविष्य तय करने में तुम्हारी समस्या, तुम्हारा सवाल और तुम्हारा सुझाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों समय अलग हैं, चुनौतियां अलग हैं और संवाद के माध्यम भी बदल चुके हैं, लेकिन मूल भावना वही है- युवा पर विश्वास।

कांग्रेस ने युवाओं को जोड़ा और आगे बढ़ाया

कांग्रेस के इतिहास को देखें तो युवा शक्ति पर यह भरोसा नया नहीं है। राजीव गांधी ने युवाओं को लोकतांत्रिक अधिकार और आधुनिक तकनीक से जोड़ा। बाद के वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने शिक्षा, कौशल और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा को आगे बढ़ाया। कमलनाथ की नजर में यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश है 'नई पीढ़ी को निर्देश देने से पहले उसे सुनना होगा। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में है। इस युवा शक्ति को यदि अच्छी शिक्षा, आधुनिक कौशल, सुरक्षित वातावरण, रोजगार के पर्याप्त अवसर और अपनी बात रखने का मंच मिले तो यही पीढ़ी आने वाले दशकों में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। राजीव गांधी ने जिस युवा भारत पर चार दशक पहले भरोसा किया था, राहुल गांधी आज उसी विश्वास को नई पीढ़ी के सवालों और आकांक्षाओं से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव गांधी के लिए वह विश्वास भारत का युवा था और कमलनाथ को राहुल गांधी की इस पहल में उसी विश्वास की गूंज सुनाई देती है- 'छात्रों की गूंज'।

दो डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही, बाकी को भी चेतावनी दी

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिमरनी। पुलिस अधीक्षक हरदा शंशाक के कुशल मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा एवं एसडीओपी टिमरनी श्रीमती आकांक्षा तलया के निर्देशन में थाना टिमरनी द्वारा डी.जे. संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। कस्बा टिमरनी में निकलने वाले जुलूस में डीजे वाहन क्रमांक MP 41 GA 0151 चालक अजय भाटी सोडलपुर एवं डीजे वाहन क्रमांक MP46 G0696 के संचालक राजेन्द्र नायर के द्वारा बहुत तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण की गयी। उक्त डीजे संचालकों द्वारा बिना अनुमति के बाजाये जाकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही थी। थाना टिमरनी में दोनों डीजे वाहनों के विरुद्ध अपराध क्र 493/26 धारा 223(A), 324(3) BNS व 7/15 म.प्र. कोलाहल अधि. का आरोपी डीजे संचालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया के द्वारा भी शांति समिति एवं डीजे संचालकों की बैठक में आदेशित किया गया था कि डी.जे. बिना अनुमति का बाजाये एवं डीजे संचालकों ने यदि आदेश की अवहेलना की तो सभी डीजे संचालकों के विरुद्ध आसारंभिक प्रकरण पंजीबद्ध कर 1-1 लाख रुपये के बंदपत्र की राशि वसूल की जावेगी। कार्यवाही में एसडीओपी टिमरनी श्रीमती आकांक्षा तलया, विवेक निरीक्षक मुकेश गौड़, उनि संतोष श्रीवास्तव, उनि प्रियंका पाठक, उनि रामविलास करपे, प्रभार उदय सिंह, प्रभार 237 राहुल वर्मा, आर अर्जुन लौवंशी आर.अभिलेख, शैलेंद्र राजपूत एवं थाना टिमरनी स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

युवाओं के विचार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' कार्यक्रम में प्रदेशभर से चयनित 140 छात्र-छात्राओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के विचारों, सुझावों और भविष्य के उत्तराखण्ड को लेकर उनके विषयों को जाना। उन्होंने कहा कि युवाओं से प्राप्त उपयोगी और व्यावहारिक सुझावों को राज्य सरकार की योजनाओं और नीति-निर्धारण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' के विभिन्न उप-विषयों में उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। 'शिक्षा एवं युवा अवसर' विषय में मयूह भंडारी और रवीना, 'पर्यावरण, वन एवं आपदा प्रतिरोधक क्षमता' में शोरोन कपूर, 'स्वास्थ्य एवं जन सेवाएं' में सतीश कुमार, 'पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन एवं रोजगार' में माही बलाई, 'सड़क, संपर्क एवं आधारभूत संरचना' में श्रितिका रावत, 'प्रौद्योगिकी एवं सुशासन' में प्रियांशु सज्जवान, 'पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था' में दृष्टि चैहान तथा 'महिला एवं बाल कल्याण' विषय में अनुष्का नेगी विजेता रहे। मुख्यमंत्री ने चयनित सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि 'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन' अभियान में प्रदेश के 2 लाख 67 हजार 744 विद्यार्थियों ने अपने निबंध, विचार और सुझाव साझा किए। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की भागीदारी दर्शाती है कि उत्तराखण्ड का युवा अपने राज्य के भविष्य और विकास को लेकर जागरूक और गंभीर है। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, वन एवं पर्यावरण, खेल, पलायन, स्वरोजगार, स्टार्टअप तथा गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव दिए हैं। युवाओं की सोच और नवाचार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।



झीरम कांड के फैसले से नाखुश सर्व आदिवासी समाज

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह, जगदलपुर। 25 मई 2013 को दरभंगा के झीरम घाटी में घटे नक्सल मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर बस्तर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। आदिवासी समाज ने जगदलपुर के परपा में स्थित कोया कुटमा भवन में बैठक की और इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने का प्रस्ताव रखा। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने फैसले पर विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर का कहना है कि जिन 10 लोगों को अदालत ने झीरम घाटी मामले में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है, वे निर्दोष हैं और उनका नक्सल संगठन से कोई संबंध नहीं था। ये लोग अपने घरेलू और रोजमर्रा के कामकाज के जरिए जीवन-यापन कर रहे थे। इसी दावे को लेकर अब आदिवासी समाज मामले को उच्च न्यायालय और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। फैसले के विरोध में बस्तर संभाग में बड़े स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। समाज की ओर से इस कानूनी लड़ाई और आगे की गतिविधियों के लिए बस्तर संभाग के प्रत्येक घर से 20-20 रुपये का सहयोग जुटाया जाएगा।

कब हुआ था झीरम कांड?

दरअसल 25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर माओवादी हमला हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत कई प्रमुख नेताओं सहित 29 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी और लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद 5 सितंबर 2026 को अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। इसके बाद 16 सितंबर 2026 को अदालत ने सभी 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

सम्पादकीय

इंदौर में राहुल गांधी का युवाओं से संवाद

इंदौर में राहुल गांधी का युवाओं से संवाद केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यापक प्रश्न की ओर ध्यान खींचने वाला अवसर है कि देश और प्रदेश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर किन मुद्दों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती है। 19 सितंबर को आयोजित 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं की रोजमर्रा की चुनौतियों पर बातचीत हुई। युवाओं के साथ संवाद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवा केवल किसी राजनीतिक दल के संभावित समर्थक नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, तकनीक, उद्यमिता और सामाजिक बदलाव के प्रत्यक्ष भागीदार हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के लिए यह समझना जरूरी है कि युवा क्या चाहते हैं, किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और भविष्य के भारत को लेकर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इंदौर में यह संवाद इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कार्यक्रम से पहले छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अपने अनुभव, समस्याएं और सुझाव साझा करने की अपील की थी। कार्यक्रम को छात्रों की सामूहिक आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा और रोजगार आज युवाओं के सामने जुड़े हुए दो प्रमुख विषय हैं। उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के साथ रोजगार की गुणवत्ता, कौशल विकास और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में समयबद्धता और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी सार्वजनिक विमर्श के महत्वपूर्ण विषय हैं। इंदौर के संवाद में इन मुद्दों पर युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी इस बहस को अधिक वास्तविक आधार दे सकती है। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता केवल भीड़ या राजनीतिक माहौल से तय नहीं होती। संवाद की वास्तविक कसौटी यह होगी कि युवाओं की बात कितनी गंभीरता से सुनी जाती है और सामने आए प्रश्नों पर कितने ठोस सुझाव प्रस्तुत होते हैं। युवाओं को केवल राजनीतिक भाषणों

के श्रोता के रूप में देखने के बजाय नीति निर्माण से जुड़े प्रश्नों पर सक्रिय भागीदार बनाना लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत कर सकता है। इंदौर का कार्यक्रम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मध्यप्रदेश में युवाओं को लेकर अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर गतिविधियां चल रही हैं। हाल के दिनों में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने युवाओं के साथ संवाद के कार्यक्रम किए हैं। ऐसे वातावरण में राहुल गांधी का छात्र संवाद युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला सकता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि युवाओं की आकांक्षाएं किसी एक विषय तक सीमित नहीं हैं। एक युवा के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण उद्यमिता, तकनीकी कौशल, मानसिक दबाव से निपटने की क्षमता, डिजिटल अवसर, खेल, नवाचार और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषय भी हैं। ग्रामीण और शहरी युवाओं की चुनौतियां भी अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए युवा संवाद का दायरा जितना व्यापक होगा, उससे निकलने वाली तस्वीर उतनी ही उपयोगी होगी। राजनीतिक नेतृत्व के लिए युवाओं से संवाद का अर्थ केवल अपनी बात रखना नहीं, बल्कि असहमति और कठिन सवालों को सुनना भी है। यदि युवा शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली या रोजगार को लेकर प्रश्न उठाते हैं तो उन प्रश्नों के तथ्यात्मक और नीतिगत उत्तर सामने आना आवश्यक है। इसी से संवाद और राजनीतिक प्रचार के बीच अंतर स्पष्ट होता है। इंदौर में 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। अब इस संवाद का महत्व इस बात में होगा कि युवाओं की आवाज कितनी स्पष्टता से सामने आती है और उससे शिक्षा, रोजगार तथा अवसरों को लेकर सार्वजनिक बहस कितनी ठोस बनती है। लोकतंत्र में युवा केवल भविष्य नहीं होते वे वर्तमान के भी महत्वपूर्ण हिस्सेदार होते हैं। इसलिए उनकी आवाज को सुनना और उस पर गंभीरता से विचार करना किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की आवश्यकता है।

सियासी गहमागहमी

कांग्रेस नेता कमलनाथ को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा ने मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि किसी नई जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक घोषणा सामने आने तक इसे राजनीतिक अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। कमलनाथ का लंबा राजनीतिक अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन तथा सरकार में निभाई गई भूमिकाएं उन्हें कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में स्थान देती हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर चुके कमलनाथ को संसदीय राजनीति का भी लंबा अनुभव है। वे कई बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व संभाल चुके हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने संगठन का नेतृत्व किया। ऐसे में यदि पार्टी नेतृत्व उन्हें भविष्य में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपता है, तो यह उनके राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय होगा। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए भी किसी वरिष्ठ नेता को सई भूमिका देना संगठनात्मक पुनर्संरचना और आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी का हिस्सा हो सकता है।

राजेंद्र शुक्ला पर कार्रवाई से क्यों बच रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव?

मध्यप्रदेश की राजनीति में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को लेकर उठ रहे सवालों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने भी जवाबदेही का प्रश्न खड़ा किया है। विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि जिन मामलों में प्रशासनिक या विभागीय स्तर पर गंभीर प्रश्न सामने आते हैं, वहां जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है। हालांकि किसी व्यक्ति पर दोष तय करना जांच और आधिकारिक निष्कर्ष का विषय है। हाल के दिनों में स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े मामलों को लेकर सरकार को कई मोर्चों पर स्पष्टीकरण देना पड़ा है। भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मामले में मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आने के बाद दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया और जांच शुरू की गई। वहीं सागर की जहरीली शराब त्रासदी के बाद भी सरकार ने लापरवाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। ऐसे में राजनीतिक बहस का मूल सवाल यह होना चाहिए कि जवाबदेही केवल मिचले स्तर तक सीमित रहेगी या प्रशासनिक निर्णयों की पूरी शृंखला को भी निष्पक्ष समीक्षा होगी। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो पद या राजनीतिक हैसियत से परे नियमानुसार कार्रवाई होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत करता है। मुख्यमंत्री के लिए चुनौती यही है कि सरकार की कार्रवाई पारदर्शी दिखाई दे और किसी भी व्यक्ति को संरक्षण दिए जाने की धारणा को तथ्यात्मक जांच से दूर किया जा सके। अंतिम निष्कर्ष जांच और आधिकारिक कार्रवाई के आधार पर ही निकलेगा।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

सरकार के पास दिया जलाने के लिए पैसा है - हमारे हॉस्टल के लिए खोती नहीं?"

यह सवाल कल इंदौर में एक छात्र ने मुझसे पूछा।

गाँव से पढ़ने आए हैं। हॉस्टल है नहीं, तो PG में रहना पड़ता है। सिर्फ सुरक्षित रहने में लाखों खर्च हो जाते हैं। हर महीने किराए की धिंता, और बेघर होने का डर - इसी ने पढ़ाई करनी पड़ती है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi



जनमान्यता श्री राहुल गांधी ने पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश के छात्रों और युवाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति आदर्शित कर दिया है।

इंदौर में छात्रों की मूज के माध्यम से राहुल जी ने प्रदेश की शिक्षा

व्यवस्था, नौकरियों में घोखाधड़ी, नौकरी से जुड़े छोटालों, कांग्रेस सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में दिए गए 27% आरक्षण को जानबूझकर लागू न करने जैसे विषय छात्रों के मुँह से ही देश के सामने रखवा दिए।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

ज्ञानी जैल सिंह: साधारण पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति भवन तक का सफर

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा केवल सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, जनसेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही है। भारत के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ऐसे ही नेताओं में शामिल रहे। एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, पंजाब की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में गृह मंत्री का दायित्व संभाला तथा अंततः देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के संघवां, तत्कालीन फरीदकोट क्षेत्र में हुआ था। उनका मूल नाम जरनैल सिंह था। बचपन से ही उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना दिखाई देने लगी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में वे ब्रिटिश शासन के विरोध में सक्रिय हुए और विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। संसद के अभिलेखों में उनके स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े संघर्ष और कारावास का उल्लेख मिलता है। 1946 में फरीदकोट में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और गिरफ्तारी दी।

स्वतंत्रता के बाद उनका राजनीतिक जीवन पंजाब और उससे जुड़े सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ा। उन्होंने पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन की अंतरिम सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में कृषि तथा लोक निर्माण विभाग से जुड़े दायित्व भी संभाले। उनका राजनीतिक अनुभव लगातार व्यापक होता गया और वे पंजाब की राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए।

ज्ञानी जैल सिंह की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाते हुए 1972 में राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1977 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल में भूमि सुधार और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे विषयों पर काम हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में उनका जोर प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े कार्यों पर रहा। संसद के अभिलेखों में भी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल और भूमि सुधारों में योगदान का उल्लेख मिलता है। उनकी राजनीतिक शैली में जनसंपर्क और सहज व्यवहार की विशेष भूमिका रही। वे आम लोगों के बीच सहजता से घुलने-मिलने के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक जीवनी में भी उनके विनम्र व्यक्तित्व और गरीब तथा वंचित वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

1980 में ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। गृहमंत्री के रूप में उन्हें आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सहित अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों से जुड़े दायित्व संभालने पड़े। संसद के अभिलेखों में उनके गृह मंत्री के रूप में प्रशासनिक कौशल और राजनीतिक अनुभव का उल्लेख किया गया है। 25 जुलाई 1982 को ज्ञानी जैल सिंह ने भारत के सातवें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे और आधिकारिक राष्ट्रपति भवन प्रोफाइल के अनुसार, पिछड़ी जाति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति भी थे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दौर में रहा। 1984 में पंजाब में गंधी आशांति और आतंकवाद की स्थिति बनी। इसी वर्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह ने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। 1985 में संसद को दिए अपने अभिभाषण में उन्होंने देश की एकता और अखंडता के सामने मौजूद चुनौतियों तथा राष्ट्रीय परिस्थितियों का उल्लेख किया था। ज्ञानी जैल सिंह का व्यक्तित्व राजनीतिक पदों से आगे उनकी सहजता और मानवीय संवेदनशीलता के लिए भी याद किया जाता है। संसद के श्रद्धांजलि अभिलेख में उनके विनम्र स्वभाव, भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि और तनावपूर्ण परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने की क्षमता का उल्लेख है। उन्हें पंजाबी साहित्य में विशेष रुचि थी और पत्रकारिता तथा लेखन में भी उनकी दिलचस्पी रही।

बिना बड़े चीरे के लेजर से किडनी स्टोन का इलाज, RIRS आधुनिक विकल्प

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। कमर में बार-बार दर्द, पेशाब में खून या जलन को नजरअंदाज करना किडनी स्टोन का संकेत हो सकता है। आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रवेश गुप्ता के अनुसार, आधुनिक चिकित्सा में किडनी की पथरी के उपचार के लिए RIRS (Retrograde Intracanal Surgery) और लेजर तकनीक प्रभावी विकल्प हैं। डॉ. गुप्ता 1000 से अधिक प्रक्रियाएं कर चुके हैं। RIRS में शरीर पर बड़ा चीरा लगाए बिना पेशाब के प्राकृतिक रास्ते से पतले उपकरण को किडनी तक पहुंचाया जाता है और



लेजर की मदद से पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इससे कई मरीजों में रिकवरी अपेक्षाकृत तेज हो सकती है। हालांकि, हर पथरी में RIRS की जरूरत नहीं होती। पथरी के आकार, स्थान और मरीज की स्थिति के आधार पर दवा, ESWL, RIRS या PCNL में से उपचार चुना जाता है। विशेषज्ञ के अनुसार, तेज दर्द के साथ बुखार, ठंड लगना, पेशाब में रुकावट या पेशाब की मात्रा अचानक कम होना गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसे में तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है। पथरी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीना, अधिक नमक से बचना और संतुलित आहार अपनाना महत्वपूर्ण है।

अब 25 हजार रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी आएंगे EPFO के सुरक्षा कवच में

-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह, ग्वालियर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सामाजिक सुरक्षा दायरे को और व्यापक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य सदस्यता के लिए वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से देशभर में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में आने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ की अनिवार्य सदस्यता के लिए वर्तमान वेतन सीमा वर्ष 2014 में 15,000 निर्धारित



की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त सत्य वर्धन गौतम ने बताया कि यह निर्णय कामगारों के हित में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में 15,000 से अधिक वेतन पर रोजगार में आने वाला नया कर्मचारी स्वतः अनिवार्य ईपीएफ के दायरे में नहीं आता है। वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 किए जाने से अब 15,000 से 25,000 तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे ईपीएफओ का दायरा बढ़ेगा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहने की स्थिति पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा।

पर्यावरणविद डॉ. प्रशान्त सिन्हा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

-संवाददाता

जगत प्रवाह, नई दिल्ली। पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए निरंतर उत्कृष्ट कार्यों के लिए पर्यावरणविद प्रशान्त सिन्हा को 'इंडोनेशिया एक्सीलेंस अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है।



यह सम्मान निरूणा ग्रीन इंडिया फैमिली, इंडोनेशिया के डायरेक्टर है एचआरएम किंग, प्रोफेसर डॉ. सम्पद रतापटाय द्वारा प्रदान किया गया। यह उपलब्धि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति संरक्षण के प्रति डॉ. प्रशान्त सिन्हा के संकल्प को और मजबूत करती है। पर्यावरण गौरव, पर्यावरण रत्न, जलयोद्धा, जल प्रहरी आदि दर्जनों सम्मान से सम्मानित डॉ. प्रशान्त सिन्हा पर्यावरणविद के अलावा लेखक भी हैं। उनके लेख जगत प्रवाह साप्ताहिक अखबार में भी छपते आए हैं।

आदतन अपराधी की मां का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, 315 बोर राइफल जब्त करने का आदेश

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, सागर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर बण्डा थाना क्षेत्र की निवासी शीलादेवी लोधी को शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही बण्डा थाना प्रभारी को लाइसेंस में दर्ज 315 बोर राइफल को तत्काल थाने में जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि, पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, बण्डा निवासी आरोपी मनीष लोधी उर्फ यशवंत (पिता कोमल लोधी) एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तथा आसूस एक्ट के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में उसके खिलाफ जहरीली शराब के निर्माण एवं विक्रय के गंभीर अपराध में मामला दर्ज किया गया था, जिसके सेवन से कई लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मनीष लोधी अपनी मां शीलादेवी के नाम पर दर्ज शस्त्र लाइसेंस (क्रमांक 94/2023) का दुरुपयोग कर आम जनता को डराता-धमकाता था और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंसधारक शीलादेवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। शीलादेवी ने अपने जवाब में कहा कि उनका पुत्र उनसे अलग रहता है और लाइसेंस का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। हालांकि, प्रस्तुत तथ्यों, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और आपराधिक इतिहास का अवलोकन करने के बाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब को असंतोषजनक पाया। भविष्य में शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है।

देश में उाती विदेशी सभ्यता की दुकानें



रघु ठाकुर

सामाजिक कार्यकर्ता,
विचारक और
समाजवादी नेता

पिछले दिनों भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि देश में 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देगे और जून माह तक 15 विदेशी विवि को अनुमति दी जा चुकी है। विदेशी विवि को अनुमति के पीछे औपचारिक कारण या तर्क यह बताया जा रहा है कि जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते थे उनके ऊपर औसतन 80 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च होता था और अब यह खर्च बच जायेगा। यह भी कि जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं उनमें से मुश्किल से 1 प्रतिशत विद्यार्थियों को विदेशों में रोजगार मिल पाता है। यह दोनों बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं और यह भी है कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश अपने यहां पढ़ने आने वाले लोगों को स्थाई रूप से बसने में कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं। जैसे पहले अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र के लिए पढ़ाई के बाद वहां रहकर नौकरी तलाशते रहने की समयवधि कई वर्ष थी परंतु अब अमेरिका ने घटाकर 1 से 3 माह कर दी और इतने में अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें देश वापिस आना होगा। वीजा नियमों में भी काफी सख्ती की जा रही है और उसका कारण है कि अब अमेरिका भी

बाहर से आने वालों के बोझ सहने से मुक्त होना चाहता है तथा अमेरिका की बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिये अमेरिकी नौजवानों को अधोषित पात्रता देना चाहती है। श्री डॉनल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में फिर से वह पुराना नारा दुहराया जाने लगा है। अमेरिकन फस्ट या वी अमेरिकन, बाय अमेरिकन। इतना ही नहीं अब बाहर के देशों से गये हुये लोग अपने आपको पहले जैसा सुरक्षित नहीं मानते हैं। क्योंकि पिछले वर्षों में डेट क्राइम की घटनायें बढ़ी हैं। जिसका शिकार कुछ भारतीय परिवार भी हुये हैं। ऐसी घटनायें अब ब्रिटेन में भी शुरू हुई हैं और वहां भी बदलाव आ रहे हैं।

1950 के बाद से अमेरिका भारतीयों और विशेषतः भारत के श्रेष्ठी वर्ग का प्रिय देश रहा है। भले ही देश की सरकार और अमेरिकन सरकार में वैचारिक फर्क रहा हो परंतु वहां की तरक्की, सिस्टम, व्यवस्था की चर्चा भारतीय उच्च, उच्च मध्यम परिवारों में आम थी। पिछले दशकों में बहुत से भारतीय अमेरिकी नागरिक बने और वहां बस गये। उस समय भारत के बुद्धिजीवी इसका तर्क देते थे कि यह ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि भारत में योग्यता की वह कीमत नहीं मिलती जो अमेरिका में मिलती है। यह भी गर्व करते थे कि अमेरिका के वैज्ञानिक खोजों के पीछे भारतीयों का बौद्धिक योगदान है। स्वतः हर गोविन्द लाल खुराना जिन्होंने जीन्स की खोज की थी, उनका उद्घाटन किया जाता था। नासा में काम करने वाले वैज्ञानिकों का उल्लेख किया जाता था परंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब अमेरिका में वीजा लेने के लिये या नागरिकता लेने के लिये अप्रवासियों से पैसा वसूला जा रहा है। जिस व्यक्ति को वहां की नागरिकता चाहिये उसको योग्यता के आधार पर प्रवेश नहीं है बल्कि धन और पूँजी के आधार पर प्रवेश मिलेगा। ऐसी स्थिति यूरोप के सभी देशों में बन रही है और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि अब उन देशों में आबादी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बहुत संभव है इन्हीं परिस्थितियों के दबाव में भारत सरकार ने यह नई नीति

बनाई है जो कि उनके घोषित स्वदेशी नारे के खिलाफ है। एक तरफ भारत सरकार व उनके नियंत्रक कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और दूसरी तरफ भारत के छात्रों को पढ़ाने के लिये विदेशी गुरु आयेंगे। पर हमारे देश में इन बातों पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, क्योंकि सब चलता है, यह संस्कृति उभर रही, पर इनके पीछे अंदरूनी कारण कुछ और हैं।

अब सरकार से यह पूछा जा रहा है कि जो विवि देश में आ रहे हैं इनका पाठ्यक्रम कौन तय करेगा? जाहिर है कि इन विदेशी विवि के जो पाठ्यक्रम वहां के हैं, वही चलेंगे। एक तरफ यही सत्ताधीश कहते हैं कि अंग्रेज के लार्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा को नष्ट किया है और अपने लिये बाबू तैयार करने के लिये शिक्षा का ढाँचा बनाया। दूसरी तरफ अब यही लोग लार्ड मैकाले को, विदेशी शिक्षा को वापिस भारत ला रहे हैं। भारतीय शिक्षा की स्थिति यह है कि भारत का एक भी विवि विश्व की गणना में शीर्ष में शामिल नहीं हो पाता।

इसके अलावा जो दो अन्य तर्क दिये गये हैं उनका पड़ताल जरूरी है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग 5.50 लाख विद्यार्थी भारत में ही विधिवत शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और बाहर रहने किराये आदि या खर्च आदि में लाखों रुपया बचेगा। मुझे इस आंकड़े पर कोई आपत्ति नहीं है परंतु दूसरा पहलू देश जानना चाहेंगे कि जो यह विवि यहां आ रहे हैं उन्हें इससे कितना लाभ होगा? अगर एक विद्यार्थी की फीस तीन-चार वर्षों में साल के 10 लाख रुपये के हिसाब से मान लिया जाये जो कि कम ही है तो एक वर्ष में इन विद्यार्थियों की फीस से न्यूनतम 5 लाख करोड़ बच जायेगा और चार वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपया विदेशों में फीस के रूप में जायेगा। यह आंकड़ा भी मैंने मात्र 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष की फीस पर जोड़ा है। हालांकि अलग-अलग विवि के अलग-अलग रेट हैं। कुछ विवि की फीस तो साल में करोड़ों रुपयों की है। दूसरे ये जो विद्यार्थी जहां पात्र होंगे, इनमें से जो विदेशी सरकारों के जरूरत के होंगे

वे, उन्हें ही वे ले जायेंगे, बकाया भारत में ही अपने रोजगार की संभावना तलाशेंगे। भारतीय लोगों का विदेशों में काम करने का या बड़ी नौकरी करने का प्रतिशत मुश्किल से 20 प्रतिशत रह जायेगा। 80 प्रतिशत नौजवान याने लगभग 04 लाख नौजवान भारत में ही रहकर नौकरी की तलाश करेंगे। उनकी जीवनशैली, मानसिक और जरूरतों के हिसाब से कितनों को भारत में रोजगार मिल पायेगे, यह भी एक सवाल है? एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि तकनीकी अध्ययन व ज्ञान के लिये छात्र विदेशी संस्थाओं के क्लाउड का इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उस तकनीकी की खोज और उसका ज्ञान इन्हें उस रूप में नहीं हो सकेगा, बल्कि प्रकार से निर्भरता स्थाई रूप से पैदा होगी।

पाश्चात्य का विदेशी संस्कृति को अभी ये भारतीय छात्र बाहर जाकर देखते और सीखते थे अब देश में ही बन रहे इन विदेशी टापुओं में ये लाखों छात्र जब विदेशी जीवनशैली, मानसिक संस्कार और भाषा पर निर्भर होंगे तब वे भारत के आम मानस को उसी दिशा में ले जाने के लिये प्रेरित करेंगे। अभी तक जो 5.50 लाख विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते थे वे 4-5 साल तक उस विदेशी वातावरण में रहते थे परंतु देश में लौटने के बाद वे अपने मूल को पुनरु यादकर उससे जुड़ने का प्रयास करते थे। अब हो सकता कि 5.50 लाख छात्र अपने देश के याने भारतीय छात्रों को अन्य विवि या कालेज में पढ़ रहे को उस जीवनशैली के लिये आकर्षण का केंद्र बन जाये और देश में विदेशी मानसिकता और जीवनशैली को प्रभावित करें। स्वाभाविक है कि जिन परिवारों के बच्चे होंगे, उनके परिवार भी इनसे प्रभावित होंगे।

इसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर भी अनेक रूप से पड़ेगा। अभी जो छात्र विदेशों से पढ़कर आये हैं वे देश की राजनीति को विदेशी राजनीति के पैमाने से देखते हैं उनके विदेशों में राजनैतिक प्रचार, राजनीति दृष्टिकोण और सोचने के तरीके बदलेंगे।

जो भारत वसुधैव कुटुम्बक की सोच पर, समरसता चाहता है। गरीब-अमीर के भेद को मिटाना चाहता है और अभी तक भारतीय राजनीति के चुनाव के आधार इस आधार पर होते रहे हैं वे मापडंड बदले जा सकते हैं। और मैं, केवल अपने लिये, अपने निजी परिवार के लिये, इस दृष्टिकोण पर जा सकते हैं। विषमता को मिटाना और समता का समाज बनाना आदर्श लक्ष्य होना चाहिये वह पूँजीवादी सोच में बदल सकता है। हम अपने वर्ग के लिए जिसे सिविल सोसायटी और सेलिब्रिटी तक ही देखा जाता है संवेदनायें व मानवीय पीढ़यें यही तक सिमट सकती हैं। पहले ही देश में लाखों की संख्या में विदेशी फंडिंग प्राप्त एनजीओ कार्यरत हैं जो भारतीय राजनीति को विचारधारा से हटाकर केवल तात्कालिकता के सिद्धांत पर ले जाने के माध्यम बने हैं। हमारे देश में परंपरा रही है कि जो हमारी संस्कृति भी है कि भविष्य में पानी की आवश्यकता पड़ेगी इसलिये पहले कुआं व बावड़ी तैयार करो परंतु विदेशी पूँजीवादी विचारधारा का कहना है कि पहले कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है। जब प्यास लगेगी तब खोदेंगे। और यह पाश्चात्य दर्शन, देश, प्रकृति और मानवता के बुनियादी मूल्यों को नष्ट करने वाला है। आज एआई, चौट जीपीटी और कितने ही नये माध्यम आये हैं सेशल मीडिया पर, फेसबुक, वाट्सअप से आगे बढ़कर एक्स और इंस्टाग्राम पर पहुंचे हैं। इन सबसे देश में एक बड़े झूठ का पहाड़ खड़ा हो रहा है। तकनीक का इस्तेमाल मानवता के लिये हो यह तो स्वीकार है मगर तकनीक इंसान बनने लगे, इंसान को वैचारिक रूप से शैतान और हैवान बनाने लगे, रोजगारों को मिटाकर बेरोजगारी की फसल पैदा करने लगे, देश की पूँजी विदेश में जाने लगे तो ऐसी तकनीक व ऐसा विकास न केवल अत्याज्य है बल्कि एक कर्तव्य में राष्ट्रीय अपराध और धार्मिक दृष्टिकोण में पाप के समान है। क्या कभी सरकारें, देश अपने शिक्षा के नये खोल रही विदेशी दुकानों को इन कसौटियों पर कसेंगी?

हावड़ा में गणेश पूजा की धूम, मिनी मुम्बई सा दिखा शहर

-अमित राय

जगत प्रवाह. हावड़ा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस बार हावड़ा शहर में गणपति बप्पा की भक्ति का रंग देखते ही बन रहा है। शहर के उत्तर हावड़ा, मध्य हावड़ा, दक्षिण हावड़ा से लेकर ग्रामीण हावड़ा तक जगह-जगह भव्य पूजा मंडप तैयार कर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरे शहर का माहौल मानो मिनी मुम्बई जैसा नजर आ रहा है। उत्तर हावड़ा के सार्विक्या स्थित उड्डियापाड़ा में पिछले 27 वर्षों से गणेश पूजा का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी यहां भव्य मंडप तैयार कर विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल होने पहुंचे। वहीं, नमक गोलाघाट इलाके में आदर्श एजुकेशन कल्चर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी तथा नमक गोलाघाट मॉनिंग वॉकर समूह की ओर से गणेश मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के साथ देर शाम भक्ति गीत-संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही बुधवार को भव्य भंडारा की भी व्यवस्था की गयी थी जिसमें लगभग 4 हजार से अधिक लोग सम्मिलित हुए। पंजाब



लान्ड इलाके में भी कई पूजा मंडपों में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना की गई। इसी तरह मध्य हावड़ा के काजीपाड़ा, कुंडलबगान, कदमतला तथा पावर हाउस के आसपास गणपति पूजा को लेकर विशेष आयोजन किए गए हैं। दक्षिण हावड़ा के बेताईतला बाजार, बी. कॉलेज गेट के आसपास और शालीमार स्टेशन के नजदीक भी कई स्थानों पर आकर्षक मंडप बनाकर गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इन पूजा मंडपों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आयोजकों के अनुसार, हावड़ा में गणेश पूजा का आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार पूजा को बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया है। कई स्थानों पर विराल और आकर्षक मंडप बनाए गए हैं। पूजा के साथ सांस्कृतिक, भक्ति और मनोरंजन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जो अगले तीन से चार दिनों तक चलेंगे। गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा हावड़ा इस बार श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

चर्चा, चार्ज और चुनौती:

क्या देश में UPI क्रांति का 'हनीमून पीरियड' खत्म हो चुका है?

आज की बात

प्रवीण कुल्कर्णी
स्वतंत्र लेखक

सुबह आँख खुलते ही दूध का पैकेट लिया QR कोड स्कैन किया। नुक्कड़ पर चाय पी QR स्कैन किया। दोपहर में सब्जी खरीदी, गाड़ी में पेट्रोल भराया, रेस्तरां में खाना खाया या रात को ऑनलाइन शॉपिंग की। बस जेब से मोबाइल निकाला, पलक झपकते ही 'बीप' की आवाज आई और भुगतान हो गया। हालत यह है कि दिन के अंत में जब आप बॉलेट खोलते हैं, तो गांधी जी की तस्वीर वाले नोट जस के तस मुस्कुराते मिलते हैं, जबकि आपकी जेब से हजारों रुपये का डिजिटल लेन-देन हो चुका होता है। जिस यूपीआई हमारी उंगलियों को बिना सूँचे-समझे खर्च करने की ऐसी जादुई आदत लगा दी। आज वही यूपीआई अचानक नियमों, चार्ज और बहसों के एक अजीब चक्रव्यूह में उलझ गया है। आखिर मुफ्त क्रांति के दावों के बीच अचानक यह 'चर्चा, चार्ज और चुनौती' का दौर क्यों शुरू हुआ? आइए समझते हैं इस पूरे खेल के पीछे का सच।

भारत की जेब कब मोबाइल में समा गई, हमें पता ही नहीं चला लेकिन अब इसी UPI को लेकर देश में नई बहस छिड़ी है। केंद्र सरकार ने 15 सितंबर को नया Merchant Discount Rate यानी MDR framework घोषित किया है, जो 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत सामान्य मर्चेट को किए जाने वाले 2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा। 75,000 या उससे अधिक के भुगतान में इसकी अधिकतम सीमा 300 होगी। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि सामग्री जैसे कम मार्जिन वाले आवश्यक क्षेत्रों में 2,000 से ऊपर 0.4 प्रतिशत के बजाय केवल 5 प्रतिशत ट्रांजेक्शन MDR होगा।

आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

सबसे पहले भ्रम दूर करना जरूरी है। एमडीआर ग्राहक पर लगाया गया

यूपीआई नहीं है। आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित को 500 भेजें या 50,000 पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांसफर पूरी तरह मुफ्त रहेगा। किसी दुकान पर 2,000 तक का UPI भुगतान भी MDR से मुक्त है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPI एप्स ग्राहक से कोई platform fee या हिंडन चार्ज नहीं ले सकते और बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहक पर न डालें। छोटे दुकानदार के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। रेड्डी-पट्टी वाले, मोहल्ले की छोटी दुकान जैसे मर्चेट यदि UPI QR से महीने में 1 लाख तक प्राप्त करते हैं, तो उन पर zero-MDR जारी रहेगा। यानी यह समझना गलत होगा कि हर चाय वाले, सब्जी वाले या छोटे दुकानदार से अब प्रत्येक बड़े QR पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत काट लिया जाएगा लेकिन 1 लाख मासिक सीमा से बाहर आने वाले सामान्य मर्चेट के एल्टिजिबल 2,000 से ऊपर के भुगतान पर लागत आएगी। उदाहरण के लिए 10,000 के एल्टिजिबल यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत यानी 40 MDR होगा। यही वह बिंदु है जिस पर व्यापार जगत सवाल उठा रहा है।

21 बैंकों से शुरू हुई एक क्रांति

UPI यानी Unified Payments Interface को NPCI ने विकसित किया। अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत 21 सदस्य बैंकों के साथ हुई और उसी वर्ष अगस्त से बैंकों के UPI एप्स ग्राहकों तक पहुँचने लगे। विचार बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी था अलग-अलग बैंकों के बीच पैसे भेजने के लिए लंबी प्रक्रिया के बजाय मोबाइल से तत्काल बैंक टू बैंक ट्रांसफर।

दस वर्ष में बदला आर्थिक व्यवहार

अगस्त 2026 के NPCI ऑफेंड इसकी विशालता बताते हैं। एक महीने में UPI पर 2,450.9 करोड़ ट्रांजेक्शंस हुए, जिनकी कुल राशि करीब 29.82 लाख करोड़ थी। उस समय 752 बैंक UPI से जुड़े थे। यानी UPI अब केवल पेमेंट ऑप्शन नहीं है। यह करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की आदत है और शायद डिजिटल इंडिया की सबसे दिखाई देने वाली सफलता भी।

फिर MDR की जरूरत क्यों पड़ी?

करीब छह वर्षों से UPI मर्चेट पेमेंट्स का जोरो MDR मॉडल चल रहा था। लेकिन इतने विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए बैंकिंग

इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, फ्रॉड प्रिवेंशन, साइबर सिक्योरिटी और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगातार खर्च होता है। सरकार का तर्क है कि पेमेंट इकोसिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए बड़े मर्चेट ट्रांजेक्शंस से सीमित रेवेन्यू जरूरी है। तर्क अपनी जगह है, लेकिन व्यापारी की चिंता भी वास्तविक है। सवाल सिर्फ 0.4 प्रतिशत का नहीं, बल्कि हजारों ट्रांजेक्शंस को जोड़कर बनने वाली लागत का है। खासकर ऐसे व्यवसायों में जहाँ बिक्री बड़ी लेकिन प्रॉफिट मार्जिन छोटा होता है।

इंदौर से उठी विरोध की आवाज

देश की सबसे मजबूत व्यापारिक पहचान वाले शहरों में शामिल इंदौर में इसी मुद्दे पर विरोध सामने आया है। 23 सितंबर को 'No UPI Day' मनाने की घोषणा की गई है। अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े 125 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने उस दिन UPI स्वीकार न करने और QR/पेमेंट डिवाइस को काले कपड़े से ढकने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्टों में इससे करीब दो लाख व्यापारियों के जुड़ने की बात कही गई है। फिलहाल इसे प्रस्तावित विरोध के रूप में ही देखा जाना चाहिए। 23 सितंबर को वास्तव में कितने व्यापारी इसमें शामिल होते हैं, तभी इसकी व्यापकता स्पष्ट होगी। लेकिन इंदौर से उठी यह आवाज एक राष्ट्रीय प्रश्न जरूर खड़ा करती है।

मुद्दा UPI बनाम व्यापारी नहीं

भारत को इस बहस से बचना होगा। यह कहना सही नहीं कि अब आम आदमी के हर UPI payment पर शुल्क लग गया है लेकिन व्यापारी की हर चिंता को यह कहकर खारिज करना भी उचित नहीं कि 0.4 प्रतिशत बहुत छोटी रकम है। यह भी ठीक नहीं है। UPI की सबसे बड़ी उपलब्धि तकनीक नहीं, विश्वास है। ग्राहक को भरोसा है कि भुगतान तत्काल और मुफ्त होगा, व्यापारी को भरोसा है कि पैसा सीधे खाते में आएगा।

इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्राहक की सुविधा, व्यापारी की कमाई और डिजिटल भुगतान व्यवस्था की आर्थिक मजबूती तीनों सुरक्षित रहें। क्योंकि दस वर्षों में UPI ने केवल भुगतान का तरीका नहीं बदला है, भारत की जेब की परिभाषा बदल दी है।

अब चुनौती यह है कि जिस डिजिटल भरोसे को हमने इतनी तेजी से बनाया है, उसे शुल्क और विरोध की बहस के बीच कमजोर न होने दें।

ओजोन परत: पृथ्वी का सुरक्षा कवच, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

आज जब जलवायु संकट गहराता जा रहा है, तब प्रकृति के उस नाजुक लेकिन अनमोल आवरण की याद आना स्वाभाविक है, जो सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत केवल वैज्ञानिक शब्दावली नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की गारंटी है। इसी एहसास को ताजा करने और वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 16 सितंबर को 'विश्व ओजोन दिवस' मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन संरक्षण केवल सरकारों या वैज्ञानिकों का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। वर्तमान समय में जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र दोहन के कारण पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बन गई है। मानव की अनेक गतिविधियाँ वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। ओजोन परत का क्षरण भी उनमें से एक है। सृष्टि के प्रारंभ में मानव की आवश्यकताएँ बहुत कम थी इसलिए वह प्रकृति से स्वतः प्राप्त संसाधनों द्वारा ही अपना गुजारा कर लेता था। समय के साथ हुई प्रगति और विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। आज 21वीं शताब्दी इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की रफ्तार उनके पुनर्भरण से कई गुणा तेज है। इस प्रकार के दोहन से प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की ओर जा रहे हैं और प्रकृति में जो

एक समस्थिति कायम थी उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अनेक मानवीय गतिविधियाँ वातावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। ओजोन परत का क्षरण भी उनमें से एक है जो वातावरण को प्रभावित कर रहा है एवं इससे स्वयं मानव भी प्रभावित हो रहा है।

ओजोन परत तकरीबन 97 से 99 प्रतिशत तक पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मांट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वास्तव में पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रकाश से धरती की रक्षा करने वाली ओजोन

ओजोन दिवस: 16 सितंबर पर विशेष

परत को बचाने हेतु अपनी जिम्मेदारी को दोहराने के प्रयास के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायु मंडल की एक परत है जिसमें ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन सम्भव है। हमारी पृथ्वी पर जीवन सूर्य द्वारा प्रदान की गई कुल ऊर्जा का लगभग आधा भाग ही वास्तव में प्रभावी रूप से पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसमें से तीस प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में तथा शेष बीस प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी से बाहर चला जाता है। पृथ्वी के वायु मंडल के चारों ओर स्थित ओजोन परत के दिनों दिन कमजोर होने या उसके बड़े होते जाने से आर्कटिक में गर्मी तीव्र होने, बर्फ के पिघलने की दर, त्वचा कैंसर और इसका घातक असर के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी के रूप में सामने आने का खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी खतरे में हैं। ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए भोजन की कमी की समस्या पैदा कर रहा है। पराबैंगनी विकिरण विकासात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को बाधित कर रहे हैं जिससे फसलों की उत्पादकता कम

हो रही है। चुकी मनुष्य भोजन के लिए फसलों पर बहुत अधिक निर्भर है इसलिए एक बहुत बड़ी संभावना है कि अगर ओजोन परत की को रक्षा नहीं गया तो इससे मनुष्य को भोजन की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ सकता है।

चिली के एक अध्ययन साबित करता है कि ओजोन में कमी और यूवी विकिरण में बढ़ोतरी के साथ मेलोनीमा के मामले में 56 फीसदी और गैर मेलोनीमा त्वचा के कैंसर के मामलों में 46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसके दुष्प्रभाव से चर्म रोग, आँखों का रोग और कैंसर जैसी बीमारियाँ बढ़ेंगी। यदि हम ओजोन परत जो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, को बचाने में नाकाम रहते हैं तब तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर ओजोन परत पर पड़ा है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्याधिक दोहन, शोषण बहुत बड़ा कारण है। बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव जलवायु पर पड़ा है। ओजोन परत का लगातार क्षरण हो रहा है जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन रिकवरी का प्रमुख कारण है। इन पदार्थों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए या हमें इनके विकल्पों का उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में हम पराबैंगनी विकिरण से हानिकारक प्रभावों से अपनी रक्षा कर सकें। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएँ एवं जंगलों को बचाएँ जिससे सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर न आ सकें। तभी ओजोन परत के छेद में हो रही बढ़ोतरी को रोक जा सकता है और इसके लिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। आइए, इस ओजोन दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम प्रकृति के इस कीमती कवच को बचाएँ और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ धरती छोड़ेंगे। क्योंकि जब ओजोन बचेगा, तभी जीवन बचेगा और जब जीवन बचेगा, तभी भविष्य संवर सकेगा।



अब नेतृत्व की बारी है



नारी शक्ति वंदन

महतारी वंदन

68 लाख माताओं- बहनों के खातों
में अब तक ₹ 19,444 करोड़

महतारी सदन

महिला स्वरोजगार केंद्र के रूप में
अब तक 137 महतारी सदनों का निर्माण

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

39.49 लाख से अधिक माताओं- बहनों की
रसोई हुई धुआ मुक्त

की जिम्मेदारी है

समृद्धि | सम्मान | सशक्तीकरण

R.O. No. : 13992/ 1



रक्षाबंधन का त्योहार
विष्णु भैया का उपहार



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

Facebook: /ChhattisgarhCMO
Twitter: /DPRChhattisgarh
Website: www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर